**ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.15 से 31.03.18**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरोज बाला	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री भीम सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री अशोक चंद	01.04.15 से 15.10.16
2	श्रीमति सुनीता देवी	15.10.16 से 04.02.17
3	श्री मदन लाल	04.02.17 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	2.51
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.16
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	11.28
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिनास्टॉक स्टोर का क्रय करना	1.88
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न	4.06
6	10	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करना	1.29
7	11	13वें एवं 14वें वित्त आयोग से अनियमित भुगतान	0.59

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.05.18 से 15.05.18 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	12/2015
2016-17	02/2017	03/2017
2017-18	03/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/

अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136 दिनांक 15.05.18 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 809235 (KCCB) दिनांक 23.05.18 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत टम्बर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत टम्बर, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	698305	46899	745204	69752	675452
2016-17	675452	83337	758789	78452	680337
2017-18	680337	81254	761591	57580	704011

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत टम्बर, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	585318	3508189	4093507	3508540	584967
2016-17	584967	1522205	2107172	1313572	793600
2017-18	793600	2600058	3393658	2265736	1127922

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹704011

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1127922

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.18 को अन्तिम शेष : ₹1831933/-

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2481104.60

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : ₹71

अन्तर : ₹649243

बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
GEN-A, KCCB- 20019005089	405399.78
AAY, KCCB- 20019045523	2990.00
GRDY, KCCB- 50058330983	42879.00
RAY, KCCB- 50059698549	397.00
VKVNY, KCCB- 50058330734	11625.00
NBA, KCCB- 50060642683	7130.00
MPLAD, KCCB- 50058330789	5025.00
SDP, KCCB- 50058330723	107689.00
TSC, KCCB- 50058330836	7161.00
13 th & 14 th FC, KCCB- 50058330712	1588799.82
MMAGY, KCCB-50061163972	302009.00
कुल राशि	₹2481104.60

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.51 लाख का अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के

अन्तिम शेष में ₹649243/- का अन्तर पाया गया (विस्तृत ब्यौरा पैरे में दिया गया है)। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 35 दिनांक 15.05.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 18.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि ₹198000 एवं ₹200000 की अनुदान राशि MMAGY के कार्यों हेतु क्रमशः दिनांक 24.01.2017 एवं 12.03.2018 को खाता संख्या 50061163972 (KCCB) में प्राप्त की गई थी लेकिन इसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई थी। अतः शेष अन्तर ₹251243 का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.2 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ बहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.3 सचिव तथा प्रधान द्वारा अपने नाम से बैंक द्वारा राशि आहरित करना :-

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव तथा प्रधान द्वारा पंचायत की राशि अपने नाम से बैंक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों एवं मजदूरों को भुगतान की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) की उल्लंघना है क्योंकि उक्त नियमानुसार ₹1000/- से अधिक का भुगतान बैंक द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अतः सचिव तथा प्रधान के नाम से बैंक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आहरित राशि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

खाता संख्या	बैंक संख्या / दिनांक	प्रधान/सचिव का नाम	आहरित राशि (₹)
GEN-A, KCCB- 20019005089	783011/ 29.09.2015	श्री अशोक कुमार (सचिव)	15000.00
-do-	783013/	श्री अशोक कुमार	41000.00

	16.10.2015	(सचिव)	
-do-	783028/	श्री अशोक कुमार	3500.00
	29.12.2015	(सचिव)	
-do-	306685/	श्री अशोक कुमार	5000.00
	10.03.2016	(सचिव)	
-do-	306683/	श्री अशोक कुमार	1026.00
	10.03.2016	(सचिव)	
-do-	306694/	श्री अशोक कुमार	5000.00
	20.05.2016	(सचिव)	

5 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को गृहकर के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹15975 की राशि वसूली हेतु शेष थी , जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	25100	25100	19795	5305
2016-17	5305	50200	55505	44980	10525
2017-18	10525	50200	60725	44750	15975

2. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 से 2017-18 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹11.28 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹1127922 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के

स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.88 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹187949 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹4.06 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹406022 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का

निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार बही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए एवं व्यय से संबन्धित माप पुस्तिका सहित अन्य बांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये। कार्य में व्यय राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	निधि का नाम
1.	नि. पार्क डढ़बाल युवा क्लब टम्बर	14 th FC
2.	नि. नालियाँ पठानिया वस्ती, झमूह -1	14 th FC
3.	नि. महिला मण्डल भवन, रोपड़ी	14 th FC
4.	नि. महिला मण्डल भवन, हरिजन वस्ती झमूह	14 th FC

10 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹1.29 लाख का अनियमित व्यय:-

जांच में पाया कि निम्नलिखित कार्यों में ₹129447 की राशि स्वीकृत एवं प्राप्त की गई राशि से अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अधिक व्यय	बही खाता पृष्ठ संख्या
1	नि. नालियाँ पठानिया वस्ती झमूह -1 (2015-16)	200000/-	100000/-	153404/-	53404	65
2	नि. महिला मण्डल भवन	-	-	-	19500	-

	रोपड़ी (2015-16)				
3	नि. महिला मण्डल भवन हरिजन वस्ती झमूह (2015- 16)	-	-	-	56543 -

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135 दिनांक 15.05.18 द्वारा उक्त अधिक व्यय राशि बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 18.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक व्यय की जांच उपरान्त वास्तविक स्थिति से सूचित कर दिया जायेगा । अतः उक्त कार्यों में अधिक व्यय की गई राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से परिहार किया जाये ।

11 13वें एवं 14वें वित्त आयोग से ₹0.59 लाख का अनियमित भुगतान :-

जांच में पाया कि पंचायत द्वारा 13वें एवं 14वें वित्त आयोग से निम्नलिखित व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं था जिस कारण से निम्नविवरणानुसार ₹58650 के व्यय अनियमित थे , जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

क्र.सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
1	111 दिनांक 08.03.17	Bill No. 1173 Dated 24.02.17, M/s Rana Electronics	कुक्कर इत्यादि	5150.00	-
2	117 दिनांक 20.03.17	Bill No. 22 Dated 20.03.17, M/s Shagun Communication	वाईफाई	3500.00	-
3	119 दिनांक 20.03.17	Bill No. 273 Dated 20.03.17, M/s K.K Timber & Furniture	कुर्सियाँ	26100.00	-
4	120 दिनांक 20.03.17	Bill No. 272 Dated 20.03.17, M/s K.K Timber & Furniture	मेज इत्यादि	23900.00	-

12 13वें वित्त आयोग से सम्भावित दोहरा भुगतान :-

जांच में पाया कि वाउचर संख्या 155 माह 12/2015 में बिल संख्या 1476890 दिनांक 04.12.15, M/s HP State Civil Supply Corp. से निर्माण कार्य "लिनक रोड मेन रोड से मनी राम के घर तक" हेतु 75 बैग सीमेंट का क्रय करके ₹18825 का भुगतान किया गया था एवं वाउचर संख्या 156 माह 12/2015 में भी इसी बिल संख्या 1476890 दिनांक 04.12.15, M/s HP State Civil Supply Corp. के अन्तर्गत निर्माण कार्य "रास्ता सरूप घराल से मेन रोड" हेतु 3 बैग सीमेंट का क्रय करके ₹753 का भुगतान किया गया था। एक ही अवधि में आपूर्तिकर्ता द्वारा एक ही क्रमांक संख्या के दो बिल जारी किए गए थे जोकि संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः उक्त वर्णित क्रय बारे वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

13 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों /

अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. वहीखाते तैयार न करना ।
7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

15 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :-

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया था परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था । अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें ।

- 17 लघु आपति विवरणिका :इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 18 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)213/2018 खण्ड-1-5961-5964 दिनांक-07.09.18
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881